राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 19 मार्च 2020
दैनिक जागरण
# बिजनेस
www.jagran.com

## भूटान में एचपीसीएल का पहला पेट्रोल पंप

**नई दिल्ली** : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने बुधवार को कहा कि उसने भूटान में पहला पेट्रोल पंप स्थापित किया है। यह पंप भूटान सरकार की इकाई स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ भूटान (एसटीबीसीएल) के सहयोग ने 11 मार्च को शुरू किया गया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह पंप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। कंपनी ने एसटीबीसीएल के साथ भूटान की चुनिंदा लोकशन पर कुल 22 पेट्रोल पंप शुरू करने संबंधी करार किया हुआ है। (प्रेट्र)

सरकार बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि बीएसएनएल चलती रहे, लेकिन सभी कर्मचारियों को बनाए रखना संभव नहीं।

— रवि शंकर प्रसाद
दूरसंचार मंत्री

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेंसेक्स | 28,869.51 ▼ 1709.58 | निफ्टी | 8,468.80 ▼ 498.25 | सोना प्रति दस ग्राम | ₹ 40,241 ▲ ₹311 | चांदी प्रति किलोग्राम | ₹35,948 ▼ ₹468 | $ डॉलर | ₹74.26 ▼ ₹0.26 | क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल | $ 27.56 |

# कोरोना से पर्यटन क्षेत्र में पांच लाख करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के प्रकोप से पर्यटन क्षेत्र में तकरीबन पांच लाख करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ है। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति से संबंधित स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने पर्यटन मंत्रालय के अलावा परिवहन, रेल एवं नागर विमानन मंत्रालय के अफसरों से कोरोना से निपटने के उपायों के अलावा इससे होने वाले आर्थिक नुकसान बारे में गहन पूछताछ की। इस दौरान कुछ रेल मंत्रालय के आला अफसर को बिना पूरी तैयारी के आने के कारण समिति की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के अफसरों ने समिति को बताया कि कोरोना से इस कैलेंडर वर्ष में 70 प्रतिशत उद्योग प्रभावित हुआ है। इनमें करीब 95 फीसद लघु एवं मझोली इकाइयां शामिल हैं। उनके पास केवल 20-25 दिन का नकदी बची है। इसके बाद उन्हें कामकाज बंद करना पड़ सकता है। इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होने का खतरा है। यदि कोरोना का कहर जारी रहा तो ढाई करोड़ प्रत्यक्ष और दो करोड़ परोक्ष

**छोटी व मझोली इकाइयों पर पड़ रहा सबसे बुरा असर, करोड़ों के बेरोजगार होने का खतरा**

प्रतीकात्मक फोटो

नौकरियां जा सकती हैं। उनके परिवारों को मिला लें तो 20 करोड़ भारतीयों पर रोजी-रोटी का खतरा मंडरा रहा है। इस पर सदस्यों ने पर्यटन क्षेत्र के लिए तत्काल आपात योजनाएं बनाए जाने का सुझाव दिया।

एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षेस नेताओं को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कोरोना से लड़ाई के लिए संबोधित किया उसी प्रकार पर्यटन मंत्री व विभागीय सचिव को राज्यों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों से इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि विदेशियों के प्रवेश पर रोक से पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना के कारण पर्यटन मंत्रालय ने अपने सभी पर्यटन केंद्रों, म्यूजियम और स्मारकों को बंद कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार समिति के सदस्यों ने एयर इंडिया की विशेष रूप से तारीफ की और विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के उसके प्रयासों को सराहा। सदस्यों ने एयर इंडिया के सीएमडी से कहा कि जाकर अपने कर्मचारियों को बताएं कि हम उनके आभारी हैं। कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यद्यपि सरकार एयर इंडिया को बेच रही है। लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे संकटों से निपटने के लिए एयर इंडिया का सरकार के हाथ में रहना जरूरी है। बैठक के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों के सचिवों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सीमित करने, किराया रिफंड करने तथा लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा की सलाह देने के बाबत एडवाइजरी जारी की।

# सरकार की निगरानी में होगा मास्क का उत्पादन, आठ रुपये तक होगी कीमत

राजीव कुमार, नई दिल्ली

कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर मास्क की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने अपनी निगरानी में इसके उत्पादन का फैसला किया है। मास्क बनाने वाली कंपनियां रोजाना स्तर पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकार ने इन कंपनियों से मास्क खरीदने के लिए कीमत भी तय कर दी है। एन-95 मास्क की कीमत 40-50 रुपये की बीच होगी, तो 3-प्लाई वाले मास्क की कीमत छह से आठ रुपये होगी। सरकार इस कीमत पर कंपनियों से मास्क की खरीदारी करेगी। अगले एक माह में 2-3 करोड़ 3-प्लाई मास्क की खरीदारी सरकार करेगी। वहीं, 30-40 लाख एन-95 मास्क खरीदे जाएंगे।

बुधवार को टेक्सटाइल सचिव की अध्यक्षता में देशभर के आठ शहरों में

**सरकार को मास्क उत्पादन की रिपोर्ट हर रोज सौंपी जाएगी**

मास्क बनाने वाली कंपनियों व अन्य साझेदारों के साथ बैठक की गई। इनमें मुख्य रूप से मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कोयंबटूर, कोलकाता और अमृतसर की कंपनियां शामिल थी। बैठक में तय हुआ कि टेक्सटाइल आयुक्त के नेतृत्व में रोजाना स्तर पर मास्क के उत्पादन की निगरानी की जाएगी। कंपनियों को मास्क उत्पादन में आने वाली हर प्रकार की बाधा को दूर करने और सप्लाई चेन को सुगम रखने का काम सरकार का होगा।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अब कोरोना वायरस के इलाज के दौरान पहने जाने वाले बॉडी शूट का भी उत्पादन देश में ही होगा। अब तक भारत बॉडी शूट के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। लेकिन घरेलू स्तर पर तीन कंपनियां विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक बॉडी शूट बनाने में कामयाब हो गई है। इन कंपनियों में वडोदरा स्थित स्योर सेफ्टी, दिल्ली स्थित मनचंदा और कोयंबटूर स्थित सिट्रा शामिल हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक फिलहाल देश में हर सप्ताह 20 हजार बॉडी शूट की जरूरत है।

बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि हर व्यक्ति को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सरकार जो मास्क खरीदेगी, उसमें से एन-95 मास्क का इस्तेमाल अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए होगा। बैठक में बाजार में मास्क की मनमानी कीमत वसूले जाने की भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक अगले एक-दो दिनों में नेशनल फार्मास्यूटिकल्स अथॉरिटी (एनपीपीए) के माध्यम से मास्क की अधिकतम खुदरा कीमत तय हो जाएगी।

# बाजार में 10,000 करोड़ रुपये जारी करेगा आरबीआइ

**मुंबई, प्रेट्र** : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) इस सप्ताह शुक्रवार को ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) के माध्यम से बाजार में 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगा। देश में कोरोना संकट के बाद तंत्र की वित्तीय स्थिरता बरकरार रखने के लिए केंद्रीय बैंक यह कदम उठाने जा रहा है। एक बयान में शुक्रवार को आरबीआइ ने कहा कि कोरोना महामारी के जोखिमों के चलते वित्तीय बाजार के चुनिंदा सेग्मेंट बहुत ज्यादा दबाव में हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि वित्तीय बाजार के सभी सेग्मेंट सामान्य रूप से काम करते रहें और उनमें तरलता की कोई कमी नहीं हो। इसी को देखते हुए आरबीआइ ने इस सप्ताह शुक्रवार को सरकारी बांड्स की खरीद के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह 8.20 प्रतिशत (परिपक्वता अवधि 15 फरवरी, 2022), 7.37 प्रतिशत (परिपक्वता अवधि 16 अप्रैल, 2023), 7.32 प्रतिशत (परिपक्वता अवधि 28 जनवरी, 2024) और 7.72 प्रतिशत (परिपक्वता अवधि 25 मई, 2025) की कूपन दरों पर बांड्स खरीदेगा।

## न्यूज गैलरी

### डॉलर के मुकाबले पाउंड 35 वर्षों के निचले स्तर पर

लंदन : कोरोना वायरस के संक्रमण का गहरा असर ब्रिटेन की करेंसी पर हुआ है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उसकी विनिमय दर घटकर 1985 के बाद से अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। निवेशकों के सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर को तरजीह दिए जाने से ब्रिटिश करेंसी की वैल्यू घटी है। पाउंड स्टर्लिंग की विनिमय दर 1.9 प्रतिशत कम होकर 1.1828 डॉलर के स्तर पर आ गई। बाद में यह थोड़ी सुधर कर प्रति पाउंड 1.1861 डॉलर रही। (एएफपी)

### दिसंबर अंत तक सरकार पर 94 लाख करोड़ रुपये का कर्ज

नई दिल्ली : पिछले वर्ष दिसंबर के अंत तक सरकार की देनदारी 93 .89 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) के आखिर के मुकाबले 3 .2 प्रतिशत ज्यादा है। दिसंबर, 2019 के अंत तक सरकार के कुल कर्ज में सार्वजनिक देनदारी की हिस्सेदारी 90 .4 प्रतिशत थी। सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले डेट सिक्युरिटीज की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के मुकाबले ज्यादा रही। (प्रेट्र)

# जेट एयरवेज को 90 दिनों की मोहलत

**राहत** ▶ कोरोना संकट के चलते कंपनी ने निवेशक खोजने में देरी की दी थी दलील

## पिछले वर्ष से बंद जेट एयरवेज पर 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज

**मुंबई, प्रेट्र** : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने अस्थायी रूप से बंद पड़ी निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए और 90 दिनों की मोहलत दे दी है। कंपनी के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने 70 प्रतिशत वोट से इस मोहलत के आग्रह को अपनी मंजूरी दे दी थी। एनसीएलटी की भास्कर पंतुला मोहन और राजेश शर्मा की खंडपीठ ने सीओसी के फैसले को अपनी सहमति दे दी।

सीओसी ने 18 फरवरी को कंपनी के लिए बोली लगाने की नई समय-सीमा 10 मार्च तय की थी। दक्षिण अमेरिकी बिजनेस दिग्गज सिनर्जी ग्रुप और नई दिल्ली स्थित प्रूडेंट एआरसी पुरानी समय-सीमा के तहत बोली दाखिल करने में विफल रही थी। सिनर्जी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स पर स्लॉट के मुद्दों पर बोली से हाथ खींच लिए। उसके बाद रूस की फार ईस्ट एशिया डेवलपमेंट ने जेट एयरवेज को खरीदने में रुचि दिखाई, जिसे बोली दाखिल करने के लिए

प्रतीकात्मक फोटो

सीओसी ने 10 मार्च की नई तिथि तय की।

पिछले दिनों कंपनी ने एनसीएलटी से इस मोहलत की गुहार लगाई थी। कंपनी का कहना था कि उसे अब तक कोई उपयुक्त खरीदार नहीं मिल पाया है। कोरोना वायरस से उपजे संकट की वजह से उपयुक्त खरीदार की तलाश करने में उसे और वक्त लग रहा है। इसलिए इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए उसे अतिरिक्त 90 दिनों की मोहलत दी जाए। कंपनी पर 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और वह पिछले वर्ष अप्रैल से सेवा में नहीं है। पिछले वर्ष जून में एनसीएलटी ने कंपनी के कर्जदाताओं द्वारा इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया का दाखिल आवेदन स्वीकार कर लिया था।

## फरवरी में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या नौ प्रतिशत बढ़ी

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : फरवरी में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 8.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मुताबिक फरवरी में यात्रियों की संख्या 1.236 करोड़ रही। हालांकि इस वर्ष जनवरी में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले घरेलू विमान यात्रियों की तादाद में सिर्फ 2.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

डीजीसीए के मुताबिक फरवरी में एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गोएयर, इंडिगो, एयरएशिया और विस्तारा के पैसेंजर लोड फैक्टर (पीएलएफ) में जनवरी के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। स्पाइसजेट के चेयरमैन व एमडी अजय सिंह ने कहा कि 93 प्रतिशत के साथ कंपनी फरवरी में भी पीएलएफ के मामले में कंपनी स्पर्धियों से आगे रही है। यह लगातार 58वां महीना है जब कंपनी 90 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ बरकरार रखने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते विमानन क्षेत्र पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सप्ताहों में स्थिति में सुधार होगा।

इस बीच, एक रिपोर्ट के मुताबिक विमानन कंपनियां इस वर्ष की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च, 2020) में बड़े नुकसान से गुजर सकती हैं। सलाहकार कंपनी सेंटर फॉर एविएशन (सीएपीए) इंडिया के मुताबिक विमानन कंपनियां कोरोना संकट को देखते हुए शुरुआती चरण में कुल मिलाकर 150 विमानों का परिचालन रद कर सकती हैं। सीएपीए ने यह भी कहा कि सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया का परिचालन जारी रखने के लिए सरकार को कंपनी में 3,000 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। इसकी वजह यह है कि मौजूदा परिस्थिति में कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया को चोट पहुंच सकती है। कंपनी संभावित खरीदारों को अभिरुचि पत्र (ईओआइ) दाखिल करने के लिए 17 मार्च की समय-सीमा को पहले ही 30 अप्रैल तक बढ़ा चुकी है।

# राशन कार्ड पर मिल सकेगा एकमुश्त छह महीने का अनाज

**पासवान ने कहा, गोदामों में है पर्याप्त अनाज, सभी राज्य सरकारों को यह सुविधा देने का निर्देश**

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : देश के सभी 75 करोड़ राशन कार्डधारक अपने कार्ड पर एकमुश्त छह महीने का अनाज ले सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में अनाज के उपलब्ध भंडार को देखते हुए सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया है। अभी राशन कार्ड पर दो महीने का एडवांस अनाज मिलता है। पंजाब सरकार छह महीने का एकमुश्त अनाज लेने की सुविधा देती है।

पासवान ने कहा कि सरकारी गोदामों में पर्याप्त अनाज है। अभी कुछ मात्रा में गेहूं को खुले में रखा गया है। ऐसे में एकमुश्त ज्यादा अनाज उठने से गोदामों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 435 लाख टन अतिरिक्त अनाज है। इसमें 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूं है। अप्रैल में पीडीएस की जरूरत करीब 135 लाख टन चावल और 74.2 लाख टन गेहूं की है। सरकार के पास पर्याप्त आपूर्ति है और राज्य एडवांस में अनाज उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण घबराहट में राशन की दुकानों पर भीड़ बढ़ने जैसी स्थिति में राज्यों को सभी जरूरी सुरक्षात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

राम विलास पासवान फाइल फोटो

### साबुन, क्लीनर और थर्मल स्कैनर की कीमतों पर नजर

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार साबुन, फ्लोर क्लीनर और थर्मल स्कैनर की कीमतों पर नजर बनाए हुए है। कोरोना के चलते देश में इनकी मांग बढ़ गई है। आमतौर पर उपभोक्ता मामले मंत्रालय 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर निगरानी रखता है। हाल ही में मंत्रालय ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को इस श्रेणी में शामिल किया है। देशभर में 114 केंद्रों के माध्यम से इन उत्पादों की कीमत पर नजर रखी जा रही है।

# विकासशील सदस्य को 45,500 करोड़ रुपये की मदद देगा एडीबी

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : एशियाई विकास बैंक (एडीबी) अपने विकासशील सदस्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 650 करोड़ डॉलर (करीब 45,500 करोड़ रुपये) की वित्तीय मदद देगा। बैंक ने कहा कि इस शुरुआती पैकेज का मकसद विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) को कोरोना से लड़ने के लिए तत्काल मदद मुहैया कराना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित यह बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करता है।

इस वर्ष सात फरवरी से एडीबी अपने विकासशील सदस्य देशों को 22.5 करोड़ डॉलर (करीब 1,575 करोड़ रुपये) की मदद दे चुका है। एडीबी के प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा ने कहा कि यह महामारी एक बड़े वैश्विक संकट में तब्दील हो गई है। इससे निपटने के लिए अब क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य रूप से कम उठाने की जरूरत है। हम अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने के लिए आक्रामक नीतियों की एक सूची तैयार कर रहे हैं। इसका मकसद हमारे भौगोलिक कार्यक्षेत्र में गरीबों, संक्रमण के आसान शिकार और जनसंख्या के अन्य तबके को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि 650 करोड़ डॉलर का यह शुरुआती पैकेज सदस्य देशों के साथ विमर्श के बाद तय किया गया है। असाकावा के मुताबिक एडीबी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, क्षेत्रीय सहकारी बैंकों, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य सभी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अपने नजदीकी सहयोग को और मजबूत करने में जुटा है।

# फ्लिपकार्ट का ऑर्डर रद कर लखपति बने

उमरिया, नईदुनिया प्रतिनिधि

**गलती से 22 खातों में पहुंच गए एक करोड़ रुपये, खाताधारकों ने कर दिया खर्च, बैंक के 60 लाख रुपये अब भी फंसे**

अभी तक ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बैंक की गफलत से 22 लोग बैठे-बिठाए लखपति हो गए। असल में इन लोगों ने ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी की थी, और किन्हीं वजहों से ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे। ऑर्डर रद करने पर बैंक ने 22 खातों में कई बार रकम लौटा दी। इस गलती से 22 खातों में लगभग एक करोड़ रुपये चले गए।

खुशी से फूले कई खाताधारकों ने आनन-फानन में अपने खाते में आई रकम का उपयोग भी कर लिया। अब बैंक पैसा वसूलने में जुटा है। यह मामला उमरिया जिले के पिनौरा में सेंट्रल बैंक का है। इस बैंक में महुरा निवासी 22 लोगों के खातों में फ्लिपकार्ट द्वारा लौटाई गई रकम को बार-बार जमा कर दिया गया। इस बारे में मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के पिनौरा स्थित

### किसी ने खरीदी बाइक, कहीं कराई गई एफडी

जब लोगों के खाते में 20 से 25 लाख रुपये तक आ गए तो कुछ लोगों ने मोबाइल और बाइक खरीद ली, जबकि कुछ लोगों ने रकम को निकालकर उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट करा दी। मामले की जांच के लिए सेंट्रल बैंक के मुंबई ऑफिस से भी एक टीम आने वाली है। टीम जांच करेगी कि यह सब कैसे हुआ।

सेंट्रल बैंक के प्रबंधक सोमरंजन बहरा का कहना था कि तकनीकी त्रुटि से ज्यादा बार रुपये बैंक ग्राहकों के खातों में चले गए हैं। ऐसा सेंट्रल ऑफिस की गलती से हुआ है। रकम की रिकवरी कराई जा रही है। अभी जांच की जा रही है।

**पहले ऑर्डर, फिर निरस्त** : सेंट्रल बैंक बिनौरा के 22 खाताधारकों ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदारी की थी। सभी 22 लोगों ने भेजी गई वस्तु पसंद नहीं आने पर उसे वापस लौटा दिया और फ्लिपकार्ट से रकम वापसी की मांग की। फ्लिपकार्ट ने इन सभी खाताधारकों को जब पैसा लौटाया तो 22 खाताधारकों के खाते में कई बार पैसे डाल दिए गए। इस तरह करीब एक करोड़ की रकम 22 खाताधारकों को मिल गई, जबकि इन खाताधारकों ने लगभग एक लाख रुपये का ही ऑर्डर निरस्त किया था।

**अब तक 40 लाख वसूले** : मामला इसी साल जनवरी का है और तब से अभी तक बैंक के अधिकारी गुपचुप ढंग से रिकवरी के लिए खाताधारकों के घर के चक्कर काट रहे थे। अब बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक 40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। शेष रकम लगभग 60 लाख रुपये अभी भी फंसे हैं।

# एनपीए के फंदे को ढीला करने की कवायद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

**छोटे व मझोले उद्योगों को खास तौर पर राहत देने की होगी कोशिश**

सरकारी क्षेत्र के बैंक अभी फंसे कर्ज (एनपीए) की समस्या से पूरी तरह से निकले भी नहीं थे कि उनके सामने कोरोना की चुनौती खड़ी हो गई है। बैंकों के प्रबंधन ने इस बारे में अपना त्राहिमाम संदेश तैयार करना भी शुरू कर दिया है, जिसे अगले कुछ दिनों के भीतर ही आरबीआइ व वित्त मंत्रालय के सामने पेश किया जाएगा। इसका मजमून यही होगा कि जिन औद्योगिक सेक्टरों पर कोरोना का असर ज्यादा हो रहा है, उन्हें दिए गए कर्जे को लेकर मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किए जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) व वित्त मंत्रालय के बीच पहले से ही ऐसे उद्योगों को फौरी तौर पर राहत देने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इन विकल्पों में एनपीए नियमों में ढील प्रमुख है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई भी कंपनी या व्यक्ति 90 दिनों तक कर्ज नहीं चुकाता है तो उसके खाते को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। आरबीआइ ने अब एक नया नियम यह जोड़ दिया है कि 90 दिनों से ज्यादा एक दिन भी अगर कर्ज या उसका ब्याज चुकाने में देरी होती है तो उसे एनपीए घोषित करना होगा। बैंकों व वित्तीय संस्थानों का कहना है कि कोरोना की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है। बैंकों का आकलन है कि अभी हालात जिस तरह से बन रहे हैं उसे देखते हुए छोटे व मझोले उद्योगों (एसएमई) पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। इसलिए इनके लिए सबसे पहले एनपीए नियमों में रियायत देना जरूरी है। निर्यातकों ने बताया कि खरीदार शिपमेंट लेने से मना कर रहे हैं। यूरोप व अमेरिका के खरीदार अगले निर्देश तक शिपमेंट लेने से इन्कार कर रहे हैं। ऐसे में उनके

प्रतीकात्मक फोटो

लिए कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि अभी सब कुछ अनिश्चित है। छोटे उत्पादक व निर्यातक दोनों के कारोबार पर कोरोना का विपरीत असर है। इसलिए हम सरकार से एनपीए मामले में रियायत की मांग कर रहे हैं। कोलेटरल फ्री (बिना गिरवी) लोन की सीमा को भी बढ़ाने की मांग की जा रही है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से इसी सप्ताह सोमवार को लोकसभा में लिखित जवाब में बताया गया है कि बैंकों का एनपीए 31 मार्च, 2018 को 10,36,187 करोड़ रुपये का था जो 31 दिसंबर, 2019 को घटकर 9,58,156 करोड़ रुपये रह गया है। पिछले चार वर्षों में 5,12,647 करोड़ रुपये का एनपीए वसूला गया है। सरकार को उम्मीद थी कि वर्ष 2020-21 से एनपीए में भारी कमी आने लगेगी क्योंकि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी (आइबीसी) के तहत भी अब जल्द फैसले आने लगेंगे। लेकिन अब बैंकों को डर सता रहा है कि जिस तरह की वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा है उसे देखते हुए एनपीए की समस्या और विकराल हो सकती है।

## दहशत

बिकवाली में लगे हैं कोरोना से घबराए निवेशक, सेंसेक्स में 1710 और निफ्टी में 498 अंक की गिरावट

# तीन साल के निचले स्तर पर आ गया सेंसेक्स

**मुंबई, प्रेट्र** : घरेलू शेयर बाजारों पर छाया अनिश्चितता का बादल छंटता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनियाभर के बाजार हलकान हैं और इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर दिख रहा है। सोमवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 1709.58 अंक का गोता लगाकर 28,869.51 पर बंद हुआ। जनवरी, 2017 के बाद सेंसेक्स पहली बार 29 हजार के नीचे बंद हुआ है। एनएसई का निफ्टी भी 498.25 अंक टूटकर 8,468.80 पर बंद हुआ।

बुधवार को ओएनजीसी और आइटीसी के अलावा सेंसेक्स की सभी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। 23.90 फीसद की गिरावट के साथ इंडसइंड बैंक टॉप लूजर रहा। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों में जबर्दस्त बिकवाली देखी गई। बीएसई में वोडाफोन आइडिया का शेयर 34.85 फीसद टूटकर 3.16 रुपये पर बंद हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स भी दबाव में रहे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'रेटिंग एजेंसियों की ओर से ग्लोबल इकोनॉमी के मंदी में आने की आशंका जताए जाने के बाद एशिया और यूरोप के बाजारों में गिरावट दिखी। इसके प्रभाव में घरेलू शेयर बाजार भी तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गए। भारत में मामलों की बढ़ती संख्या और यहां कारोबार पर पड़ रहे असर से भी निवेशक परेशान हैं।' बुधवार को बीएसई में सभी सेक्टर गिरावट में रहे।

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में राहत पैकेज की घोषणा भी निवेशकों का भरोसा मजबूत नहीं कर सकी। चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और जापान के बाजारों में 4.86 फीसद तक की गिरावट आई। यूरोपीय बाजारों में भी शुरुआती कारोबार में चार फीसद तक की गिरावट देखी गई।

दुनियाभर के बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। प्रतीकात्मक फोटो

### सोना 311 रुपये उछला, चांदी में आई गिरावट

**नई दिल्ली, प्रेट्र** : शेयर बाजारों में गिरावट और रुपये में नरमी के बीच बुधवार को सोने में तेजी आई। स्थानीय सराफा बाजार में सोना 311 रुपये मजबूत होकर 40,241 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस बीच, चांदी 468 रुपये टूटकर 35,948 रुपये प्रति किलो पर बोली गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट रही।